

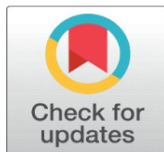
E-GOVERNANCE'S ROLE IN GENDER EQUALITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ई-गवर्नेंस की लैंगिक समानता और सतत विकास में भूमिका

Alka Sharma¹, Sanjay²

¹ Assistant Professor & Head, Department of Political Science, M.B. Government. PG College, Haldwani, Uttarakhand, India

² Research Scholar, Department of Political Science, Kumaun University, Nainital, India



ABSTRACT

English: E-governance is the integrated use of communication and information technology to deliver government information and services to a country's citizens. E-learning initiatives within e-governance, such as Google Meet, Zoom, YouTube, e-Pathshala, e-Library, e-PG Pathshala, etc., have greatly benefited women in the field of education. Through various digital platforms, women are pursuing their studies and achieving success in various fields. Various digital government schemes have had a positive impact on women. The government's e-governance schemes have made most tasks paperless. The goal of e-governance is to empower citizens through access and use of information. People, processes, technology, and resources are the key pillars of e-governance. The e-governance scheme aims to provide citizens with access to all government services through Common Service Centers. For centuries, women have been denied the right to equal participation in the nation's social and economic activities. The concept of gender equality has become a common concern, especially in India. Due to the patriarchal nature of society, women are unable to receive the respectful benefits of various government initiatives, even though India promises digital inclusion and digital opportunities. Rural India still suffers from the digital divide. Unleashing the full potential of e-governance initiatives without access to ICT is impossible. Gender differences impact connectivity and access opportunities. E-governance is not a panacea, yet it offers men and women an opportunity to overcome the social evils of gender inequality. The United Nations is holding a virtual meeting to promote sustainable development. The Declaration of the United Nations Conference on Environment and Development recognizes the right of every country to pursue social and economic progress and places on states the responsibility to adopt models of sustainable development.

Hindi: ई-गवर्नेंस किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचनाओं एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना है। ई गवर्नेंस में ई-लर्निंग पहलों जैसे गूगल मीट, जूम, यूट्यूब, ई-पाठशाला, ई-लाइब्रेरी, ई-पीजी पाठशाला आदि से शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को बहुत अधिक लाभ पहुंचा है। विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाएं अपनी पढ़ाई कर रही हैं और विभिन्न क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त कर रही हैं। सरकार की विभिन्न डिजिटल योजनाओं का महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। सरकार की ई-गवर्नेंस योजनाओं से अधिकतर कार्य पेपर लेस हो गया है। ई-गवर्नेंस का लक्ष्य सूचना की पहुंच एवं उपयोग के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण करना है। लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन ई-गवर्नेंस के प्रमुख स्तंभ हैं। ई-गवर्नेंस योजना का लक्ष्य कॉमन सर्विस सेंटरों के जरिए आम नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना करना है। सदियों से महिलाओं को राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में समान भागीदारी के अधिकार से वंचित रखा गया है। लैंगिक समानता की अवधारणा विशेष रूप से भारत में एक आम चिंता का विषय बन गई है। समाज की पितृ सत्तात्मक चरित्र के कारण महिलाएं विभिन्न सरकारी पहलों से सम्मान लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं भले ही भारत डिजिटल समावेशन और डिजिटल अवसरों का वादा करता है। ग्रामीण भारत अभी भी डिजिटल विभाजन की चपेट में है। आईसीटी तक पहुंच के बिना ई-गवर्नेंस पहल की पूरी क्षमता सामने लाना असंभव है। लिंग भेद कनेक्टिविटी और पहुंच के अवसरों को प्रभावित करते हैं। ई-गवर्नेंस कोई अमृत नहीं है फिर भी यह पुरुषों और महिलाओं को लैंगिक असमानता की सामाजिक बुराइयों से उबरने का मौका प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल

DOI

10.29121/shodhkosh.v6.i2.2025.653
2

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2025 The Author(s). This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.



बैठक कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर्यावरण एवं विकास पर घोषणा प्रत्येक देश के सामाजिक और आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने की अधिकार की मान्यता देती है और राज्यों को सतत विकास का मॉडल को अपनाने की जिम्मेदारी सौंप जाती है।

Keywords: E-governance, E-learning, Digital, Equality, Sustainable Development, ई-गवर्नेंस, ई-लर्निंग, डिजिटल, समानता, सतत विकास

1. प्रस्तावना

ई-गवर्नेंस सभी स्तरों पर सूचना तथा लेनदेन संबंधी आदान-प्रदान की क्षमता प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाब देही को बढ़ाना है। यह आदान-प्रदान सरकार तथा राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तरों की सरकारी एजेंसियों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच है। ई-गवर्नेंस का लक्ष्य सूचना की पहुंच और उपयोग के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण करना है।

नरेंद्र मोदी: मैं प्रौद्योगिकी को सशक्तिकरण के एक साधन और एक ऐसे टूल के रूप में देखता हूं जो आशा और अवसर के बीच की खाई को पटाता/ दूर करता है।

डॉ मनमोहन सिंह: भारत में ई-गवर्नेंस की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत का युवा वर्ग वैश्वीकरण के युग में बड़ा हुआ है और इसे बचपन से आधुनिक उपकरणों के माध्यम से अपना करियर बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है।

कानून के तहत समानता, अवसर की समानता, और राजनीतिक निर्णय लेने को आकार देने के लिए आवाज की समानता को लैंगिक समानता के महत्वपूर्ण आयाम माना गया है। लैंगिक समानता की संकल्पना करते समय, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि एक समूह के रूप में महिलाएँ सजातीय नहीं हैं। महिलाओं की ज़रूरतें, रुचियाँ, संसाधनों और निर्णय लेने की शक्ति पर उनका नियंत्रण उनकी कई पहचानों से आकार लेते हैं, जिनमें नस्ल, वर्ग, जातीयता, धर्म, यौन अभिविन्यास, आयु, विकलांगता आदि शामिल हैं।

महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता अलग-अलग हैं, हालांकि निकट संबंधी अवधारणाएं हैं। सशक्तिकरण का अर्थ केवल भौतिक संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाना या उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के साधन उपलब्ध कराना नहीं है। यह समान रूप से महत्वपूर्ण आत्म-प्रतिबिंब के लिए स्थितियाँ बनाने के बारे में है, ताकि महिलाएं लैंगिक समानता के संरचनात्मक आधार को समझ सकें और व्यक्तिगत और सामूहिक लाभ के लिए लैंगिक शक्ति संबंधों को बदलने के लिए अन्य महिलाओं के साथ मिल सकें। इसलिए एजेंसी, या महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति, सशक्तिकरण का 'सार' है। यह आत्मनिर्णय की दिशा में संभावित विकल्पों को समझने की क्षमता है। ई-गवर्नेंस संभावित रूप से उन संसाधनों को अधिकतम करती है जो सतत विकास स्तर को सशक्त बनाने और आभासी बैठकों, शिक्षा और अन्य गतिविधियों के दूरस्थ कामकाज और वितरण को उत्प्रेरित करने के लिए सरकारों में कार्यात्मक हैं। ई-गवर्नेंस प्रथा समय पर, विश्वसनीय तरीके से उच्च गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है, जो किसी देश को सतत विकास हासिल करने में मदद कर सकती है।

2. सहित्य समीक्षा

अनु सक्सेना 20 वर्षों से अधिक समय से लैंगिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हाशिए के समुदायों में अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में शामिल रही हैं। अनु सक्सेना भारत के ग्रामीण राजस्थान में बेयरफुट कॉलेज में एक क्रांति हो रही है। यह एक शांत क्रांति है जो सबसे गरीब ग्रामीण समुदायों तक सौर ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी लाती है, जिससे ग्रामीण विकास का चेहरा बदल जाता है। इस क्रांति में सबसे आगे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की अर्धशिक्षित या अशिक्षित ग्रामीण महिलाएं हैं, जिन्हें कुशल सौर इंजीनियरों के रूप में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

3. पर्यावरण पर विशेष प्रतिवेदक, 2023

8 march 2023 की थीम " डिजिटल: लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी " है, जो उन महिलाओं, लड़कियों को पहचानना और परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल शिक्षा की प्रगति का समर्थन कर रही हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी में प्रगति विकास, मानवीय और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने और 2030 एजेंडा के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपार अवसर प्रदान करती है। दुर्भाग्य से, डिजिटल

क्रांति के अवसर लैंगिक असमानता के मौजूदा पैटर्न को कायम रखने का जोखिम भी पेश करते हैं। उदाहरण के लिए, कई पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में लिंग और लिंग-अलग-अलग डेटा की कमी महिलाओं, लड़कियों और उनकी जरूरतों को नीति निर्माताओं के लिए अदृश्य बना देती है।

4. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA-4)

पर्यावरण प्रशासन में निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। चौथी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने पर्यावरण प्रशासन में लैंगिक समानता और मानवाधिकारों तथा महिलाओं, लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के महत्व को मान्यता दी गई है।

को, सुसान., स्टीव, रॉसन (2017) "ऑनलाइन शिक्षण एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका" पुस्तक में मोबाइल उपकरणों के साथ शिक्षण, खुले शैक्षिक संसाधनों का उपयोग और सीखने के विश्लेषण पर विस्तारित जानकारी प्रदान करती हैं। संकाय के साथ अतिरिक्त साक्षात्कार, केस अध्ययन और उदाहरण, नए टूल और टूल की श्रेणियों, विशेषकर मल्टीमीडिया पर स्पॉटलाइट। सिद्धांत के बजाय कार्यान्वयन के कैसे और क्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, टीचिंग ऑनलाइन पढ़ाने वाले या ऑनलाइन पढ़ाने के बारे में सोचने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक आवश्यक संसाधन है।

सिन्हा, संजीव (2023). ई-लर्निंग रिसर्च में ई-लर्निंग को कौशल और ज्ञान के नेटवर्क सक्षम हस्तांतरण के रूप में भी कहा जा सकता है, और शिक्षा का वितरण एक ही या अलग-अलग समय पर बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं को किया जाता है। पहले, इसे पूरे दिल से स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि यह माना जाता था कि इस प्रणाली में सीखने के लिए आवश्यक मानवीय तत्व का अभाव है। ई-लर्निंग अनुसंधान अध्ययन का एक विस्तारित और विविधीकरण क्षेत्र है। विशेषज्ञ अनुसंधान इकाइयाँ और विभाग इस पर काम कर रहे हैं। वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में ई-लर्निंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसमें पूरी शिक्षा प्रणाली को बदलने की क्षमता है और इसी कारण से यह शोधकर्ताओं के लिए सबसे पसंदीदा विषयों में से एक बन गया है। जनसंचार, शिक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) और दूरस्थ शिक्षा जैसे विभिन्न विषयों में ई-लर्निंग पर शोध कार्य चल रहे हैं। विद्वान ई-लर्निंग के विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहे हैं। यह पुस्तक उच्च शिक्षा में ई-लर्निंग को समझने के लिए एक सुसंगत, व्यापक और अनुभवजन्य-आधारित रूपरेखा प्रदान करती है।

मीनाक्षी चौधरी और विनयशील गौतम (2004), "ई-गवर्नेंस के युग में पुनर्गठन संगठन" इसमें सरकार के कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव और भूमिका की जांच की है और बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा नए बदलाव लाए हैं। उनके अनुसार ई-गवर्नेंस प्रक्रिया में सरकार इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग कर रही है। वह कहते हैं कि इसमें न केवल रणनीतियों में बदलाव शामिल है बल्कि संगठन की संरचना में भी बदलाव शामिल है। यह पत्र ई-गवर्नेंस के नए युग में संगठन की संरचना में इन परिवर्तनों को पहचानने और समझने का प्रयास करता है।

आजाद, गुलाब सिंह (2012) ने अपने अध्ययन क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण एक अध्ययन में सक्षमता, सामर्थ्यवान, सम्पन्नता, सरलता एवं सुयोग्यता जैसे घटकों की कसौटी के आधार महिला सशक्तिकरण को इस रूप में देखते हैं। महिलाएँ तकनीकी ज्ञान-विज्ञान व आध्यात्म के सामंजस्यपूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से इतनी सक्षम व कुशल बने कि वे अपनी विविधतापूर्ण वर्तमान व भावी भूमिका का निर्वाह बेहतर तरीके से कर सकें। महिलाएँ इतनी सामर्थ्यवान बने कि वे अन्याय का मुंहतोड़ जवाब दे सकें। महिलाओं को शैक्षणिक विकास व आजीविका निर्वाह के अवसरों में चयन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। महिलाएं इतनी सबल हों कि वे घर के अन्दर व बाहर अपने निर्णय स्वयं ले सकें सामाजिक-सांस्कृतिक आदि बंधन उनकी राह का रोड़ा न बन सकें।

5. उद्देश्य

- 1) जेंडर इक्वलिटी और सतत विकास में ई-गवर्नेंस की भूमिका को जानना।
- 2) सतत विकास की चुनौतियों को समझना।
- 3) सतत विकास प्रक्रिया को जानना।
- 4) ई-गवर्नेंस का प्रभाव का अध्ययन करना।
- 5) जेंडर समानता को समझना।

6. शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। इसमें विभिन्न पत्र, पत्रिकाओं एवं पुस्तकों का सहारा लिया गया है। शोध पत्र में भारत सरकार कि विभिन्न रिपोर्टों से जानकारी ली गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ और कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों की प्रकाशित रिपोर्टों कि मदद से आंकड़े लिए गये हैं।

7. महत्व

ई-गवर्नेंस तकनीकी साधनों का सही तरीके से उपयोग करके जेंडर असमानता को कम करने और समाज में समानता स्थापित करने में मदद करता है। ई-गवर्नेंस से जेंडर नेतृत्व में समानता और न्याय में सुनिश्चितता की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद कर सकती है। जेंडर इक्वलिटी के सिद्धांत में समाज में सभी व्यक्तियों को अनुकूल स्थिति और अधिकार मिलने चाहिए। ई-गवर्नेंस के माध्यम से जेंडर इक्वलिटी सुनिश्चित होती है क्योंकि इसमें लोग सरकारी योजनाएं और सुविधाओं का सीधा लाभ उठा सकते हैं। जिससे उन्हें सम्मान अधिकार और अवसरों को प्राप्त करते हैं। समस्याओं का ठीक से अध्ययन हो सके इसके लिए जेंडर इक्वलिटी से संबंधित डेटा का सही संग्रहण और प्रस्तुतीकरण भी ई-गवर्नेंस के माध्यम से सुनिश्चित हो सकता है। ई-गवर्नेंस से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं और निर्णय में जेंडर भेदभाव कम करने का सामर्थ्य होता है। इससे समाज में न्याय और अधिकारों का उपयोग करने में सहायता मिलती है और जेंडर इक्वलिटी के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है।

8. लैंगिक समानता

हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का हकदार है लेकिन उनके जीवन में लैंगिक असमानता और उनके देखभाल करने वालों के जीवन में इस वास्तविकता में बाधा है। भारत में लैंगिक असमानता के कारण अवसरों में भी असमानता उत्पन्न करता है जिसका प्रभाव दोनों लिंगों पर पड़ता है। लेकिन आंकड़ों के आधार पर देखें तो इस भेदभाव से सबसे अधिक लड़कियां अच्छे अवसरों से वंचित रह जाती हैं। अनेक शोधों में यह साबित हुआ है कि लैंगिक समानता सभी समुदायों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

लैंगिक समानता :- लैंगिक समानता की परिभाषा जिसमें अधिकारों और अवसरों तक पहुँच जेंडर से अप्रभावित होती है। यह केवल महिलाएं ही नहीं है जो लैंगिक असमानता से प्रभावित होती हैं सभी जेंडर प्रभावित होते हैं। जिसमें पुरुष, ट्रांस और लिंग विविध लोग शामिल हैं। यह बदले में बच्चों और परिवारों तथा सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों को प्रभावित करता है। जेंडर में समानता का मतलब यह नहीं है कि महिलाओं और पुरुषों के पास बिल्कुल सामान संसाधन होंगे या उनकी आवश्यकता होगी बल्कि यह है कि महिलाओं, पुरुषों, ट्रांस लोगों और जेंडर विविध लोगों के अधिकार, जिम्मेदारियां और अवसर जन्म के समय उनके निर्दिष्ट जेंडर पर निर्भर नहीं होंगे। जैसे घरों में समानता, समान कार्य के लिए समान वेतन आदि शामिल हैं। जेंडर इक्वलिटी का साक्षरता से लेकर रोजगार में समानता तक विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। समाज में सभी व्यक्तियों को सम्मान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। चाहे वह पुरुष हो या महिलाएं इससे समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।

महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ई-गवर्नेंस को एक प्रभावी सार्वजनिक नीति साधन बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं का ध्यान में रखा जाना चाहिए। नीति निर्माण कार्यान्वयन में लिंग आधारित विचार, सरकारी प्रणालियों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की शुरुआत, शासन और सार्वजनिक भागीदारी में महिलाओं को शामिल करने में पारंपरिक बाधाओं को दूर करने में मदद मिल सकती है।

लैंगिक असमानता स्वास्थ्य और विकास को कमजोर करती है। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का कहना है कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए प्रोग्रामिंग और नीति-निर्माण के सभी स्तरों पर रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इन स्तरों में प्रजनन स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण, शैक्षिक सशक्तिकरण और राजनीतिक सशक्तिकरण शामिल हैं।

लैंगिक समानता सिर्फ समान प्रतिनिधित्व से कहीं अधिक है। यह महिलाओं के अधिकारों से दृढ़ता से जुड़ी हुई है और अक्सर नीति में बदलाव की आवश्यकता होती है। वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता हासिल करने के लिए महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हानिकारक प्रथाओं को खत्म करने की भी आवश्यकता है जिसमें यौन तस्करी, स्त्री हत्या, युद्धकालीन यौन हिंसा, लिंग वेतन अंतर और अन्य उत्पीड़न रणनीतियां शामिल हैं।

9. सतत विकास

सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति दुनिया भर में प्रमुख एजेंडे में है। सतत विकास को भविष्य की पीढ़ियों के लिए उच्च जीवन स्तर और पर्यावरण को बनाए रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की जरूरत को पूरा करने के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा सतत विकास की अवधारणा धन और आय स्तर में वृद्धि के साथ सामग्री प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के अधिग्रहण के माध्यम से मानव की भलाई सुनिश्चित है।

सतत विकास का मूल सिद्धांत हरित विकास को बढ़ावा देकर किसी देश और क्षेत्र को कुशल और किफायती बनाने में लाभ पहुंचता है। सतत विकास स्तर को प्राप्त करने के लिए सरकारी संस्थागत संरचना में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ई-गवर्नेंस प्रणाली और हरित अर्थव्यवस्था को पूरा किया जा सकता है। विकास कभी भी संतुलन की स्थिति में नहीं होता है, यह समग्र प्रक्रियाओं से गुजरता है और ई-गवर्नेंस जैसे परिवर्तनों और बदलाव को संदर्भित करता है।

ई-गवर्नेंस सतत विकास प्राप्त करने के लिए वर्चुलाइजेशन और डेटा फ़िक्सन की सुविधा प्रदान करते हैं। ई-गवर्नेंस परिवर्तन के दृष्टिकोण से सरकारें अल्प विकसित देशों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, ऑनलाइन सेवाओं में सूचना एवं भागीदारी के लिए एक बढ़ता हुआ दृष्टिकोण प्रदान करती हैं जिसे, सतत विकास को बढ़ावा मिलता है।

ई-गवर्नेंस के साथ संयुक्त पहल को जनता के लिए उन्नत सुविधाओं को डिजाइन करने, पारदर्शिता, जवाबदेही, भरोसेमंदता, प्रभावशीलता, समावेशिता, खुलेपन को सक्षम करने और सतत विकास के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुँच बढ़ाने में आवश्यक तत्वों के रूप में पहचाना जाता है। नागरिकों की जरूरत के अनुसार ई-गवर्नेंस प्रणाली के माध्यम से सुशासन और अनुकूलित लचीलापन सेवाओं को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, जो एक सतत विकास के पथ को सक्षम करने में मदद करता है।

ई-गवर्नेंस एक आवश्यक उपकरण है, जो सेवा वितरण की पारंपरिक सरकारी प्रणालियों को बदलकर समाज और व्यवसायों के लिए पारदर्शी, प्रभावी और कुशल बनाता है, जिसे सतत विकास को बढ़ावा मिलता है।

सतत विकास में जनसंख्या वृद्धि जलवायु परिवर्तन और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मुद्दे भी शामिल होते हैं। हमें संवैधानिक रूप से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के साथ ही उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम प्राकृतिक संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनकी स्थिति में कमी न हो और आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार मिल सके।

विकास प्रकृति का स्वाभाविक गुण है इस लिहाज से भी मामले में स्वाभाविक विकास भी सतत प्रक्रिया है। जैसी निर्जन में कोई पौधा उग आए और बढ़ता रहे दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया और योजना बंद तरीके से उसकी दोनों ओर संघन पौधे लगवाये तथा बड़े होने तक उनकी देखभाल की गई बाद में भी उनकी शाखों की वजह से यातायात बाधित न हो इसके इंतजाम किए गए थे। यह सतत विकास का ही कांसेप्ट है।

यह भी देखना पड़ता है की प्रकृति का विनाश न हो, प्रकृति का विकास हो और साथ में आम जनता को रोटी, कपड़ा, मकान और उनकी शिक्षा और विभिन्न संस्थाओं का भी विकास होता रहे। समाज का विकास साथ-साथ प्रकृति का विनाश न हो दोनों का तालमेल बना रहे। इसे सतत विकास कहते हैं।

विकास को समझने के लिए प्रकृति के नियमों को समझना जरूरी है। महात्मा गांधी ने बार-बार दोहराया है कि हमें प्रकृति पूर्वक जीवन शैली की आवश्यकता है। गांधी जी ने स्वच्छता का महत्व बहुत पहले रेखाचित्र कर दिया था स्वच्छता इंसान के मूल स्वभाव में है। ऐसा क्या हुआ इंसान अपने मूल स्वभाव से भटक गया। गांधी का झाड़ू केवल पॉलिथीन साफ नहीं करता वह मन को भी साफ करता है। वह हमारे देश में बहुत जरूरी है क्योंकि विज्ञान ने बहुत तरक्की की है।

लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा विभिन्न रूपों में जारी है, जिनमें असमान वेतन, स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच और लिंग आधारित रूढ़ियां शामिल हैं। महिलाओं को करियर में उन्नति में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। खासकर पुरुष प्रधान उद्योगों और नेतृत्व वाले पदों पर सामाजिक मानदंड और संस्कृति दृष्टिकोण अक्सर लैंगिक असमानता को कायम रखते हैं, तथा पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को मजबूत करते हैं।

भारतीय समाज संस्कृति बहुत तथा विभिन्न दृष्टिकोण एवं हित समूहों वाला है। ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों में अन्तर विषय विकास में कमी का होना भी शामिल है। अंतर विषय निर्माण में पर्याप्त समय देना आवश्यक है। ई-लर्निंग सामग्री, उपभोक्ता मार्ग निर्देशों, स्थानीय भाषा, खुले मानदंड आदि अंतर विषय के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय भाषाओं में सामग्री का उपलब्ध नहीं होना एक बहुत बड़ी बाधा है। ई-साक्षरता का अभाव भी इसके कार्यान्वयन में रुकावट उत्पन्न करता है।

परिवर्तन का विरोध भी ई-सेवा के अनुप्रयोगों में बाधा तब उत्पन्न होती है, जब संबंधित अधिकारी परिवर्तन अथवा नवीकरण के प्रति उदासीन होते हैं या विरोध करते हैं। कार्यालय में नवीन उपकरणों को प्रयोग में लाने से पूर्व कर्मचारियों तथा अधिकारियों को प्रशिक्षित करना एवं उन्हें इस ई-सुविधा के लाभों से परिचित कराना आवश्यक है।

10. हिमालय क्षेत्र में सतत विकास की चुनौतियां

हिमालय जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं जिससे अनुप्रवाह में नदियों में जल की उपलब्धता प्रभावित हो रही है।

चोटियों और पहाड़ी ढलानों पर रहने वाले पहाड़ी लोगों के पास पीने और कृषि के लिए पानी तक सीमित पहुंच है। बताया जाता है कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र में झरने सुख रहे हैं, और पर्वतीय कृषि सूखे से प्रभावित हुई है। पानी की कमी ने पर्वतीय समुदायों विशेष कर महिलाओं पर बोझ को बढ़ा दिया है। समुदायों को जल प्रेरित प्राकृतिक खतरों के कारण संपत्ति और जीवन की हानि का सामना करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन ने भविष्य में जल की उपलब्धता और जल सुरक्षा के बारे में अनिश्चिता पैदा करके स्थिति को और खराब कर दिया है।

11. भारी निर्माण कार्य से भूस्खलन

दोषपूर्ण विकास से चमोली में भूस्खलन के बाद अवरुद्ध सड़कें, उत्तराखंड में जोशीमठ का धसना, हिमाचल के चंबा में सड़क का धसना, हिमालय क्षेत्र में संस्थागत रूप से दोषपूर्ण विकास का नतीजा है। इसरो का अध्ययन बताता है कि रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले देश में सबसे अधिक भूस्खलन प्रभावित जिले हैं।

प्राकृतिक आपदाएं हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन, हिमस्खलन और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं चुनौतियां हैं। जलवायु परिवर्तन इन घटनाओं की आवृत्ति को बढ़ा सकता है।

अनियमित पर्यटन: पर्यटन आर्थिक लाभ उत्पन्न कर सकता है, लेकिन अनियंत्रित पर्यटन स्थानीय संसाधनों और परिस्थितिकी तंत्र पर दबाव भी डाल सकता है।

दोषपूर्ण अवसंरचना परियोजनाएं जल से विद्युत का निर्माण या विकास ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। यह ऊर्जा उत्पादन का महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन इसकी दोषपूर्ण अवसंरचना के कारण अर्थात् जल विद्युत परियोजनाओं की संख्या में बढ़ोतरी और बदतर निर्माण के कारण बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है।

उपयुक्त अपशिष्ट प्रबंधन का अभाव: हिमालय क्षेत्र के शहर दिन प्रतिदिन बड़े होते जा रहे हैं और मैदानी शहरों की तरह कचरा एवं प्लास्टिक के बड़े-बड़े ढेर, अनुपचारित सीवरेज, अनियोजित शहरी विकास और यहां तक की वाहनों के कारण स्थानीय वायु प्रदूषण की स्थिति का सामना करने लगे हैं। अधिकांश पहाड़ी गांव में अपशिष्टों की सुरक्षित निपटान के लिए कोई स्थानीय, विकेंद्रीकृत सुविधा उपलब्ध नहीं है।

12. निष्कर्ष

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने पूरी धरती को एक गाँव बना दिया है। आईसीटी में विकास ने शासन के क्षेत्र में ही नहीं जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रवेश किया है, इसमें सूचना एवं ज्ञान प्रबंध के साथ सेवा वितरण में अधिक दक्षता का समावेश हुआ है। आकड़ा संचयन, भौगोलिक सूचना प्रबंधन तथा निर्माण सहायक प्रणाली द्वारा शासन व्यवस्था को अधिक गतिशील और व्यवस्थित बनाया जा सकता है। ई-गवर्नेंस में इंटरनेट तथा वेबसाइटों के माध्यम से आसानी से सूचना का अन्वेषण, संग्रहण, संचारण तथा प्रकाशन प्रसारण किया जा सकता है। ई-गवर्नेंस के रूप में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने शिक्षा के क्षेत्र में भी पर्याप्त विकास किया है। ई-लर्निंग के विकास से भौगोलिक बाधाओं से परे शिक्षा प्रदान की जा सकती है। आधुनिक वैज्ञानिक विकास द्वारा शासन के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया है वह ई-गवर्नेंस के रूप में देखा जा सकता है। सतत विकास हमें आत्मनिर्भर, प्रदूषण मुक्त और प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने की दिशा में प्रेरित करता है जिसे हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में मदद कर सकते हैं।

आजकल की तेजी से बदलती दुनिया में ई-गवर्नेंस और सतत विकास ने समाजों को एक नए दृष्टिकोण से जोड़ा है। ई-गवर्नेंस सरकारों और नागरिकों के बीच तेज और सुरक्षित जानकारी विनिमय को संभालने का एक उपाय है, जिससे समाज में सतत विकास हो सकता है। सतत विकास का मतलब है समृद्धि की दिशा में सुधार करना। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम तकनीकी और वित्तीय साधनों का सही तरीके से उपयोग शामिल है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- Hindustan time's, (2022) August 06, Politics and people don't destroy the Himalays for tourism gains 2
- The Hindu 2023, August 28, Himalayan blunders that are ravaging the Himalayas
- Misra, Udit. 2015. " How India Ranks on Gender Parity -and Why? " Indian Express. November 4.
- Nair, Shalini. 2015. " More Gender Inequality in India than Pakistan and Bangladesh: UN " Indian Express, December 15.
- Www.downtoearth.org.in
- आईसीटी और एसडीजी (2015)। [https://www.ericsson.com/res/docs/2015/ict-and-sdg-interim- रिपोर्ट.पीडीएफ](https://www.ericsson.com/res/docs/2015/ict-and-sdg-interim-रिपोर्ट.पीडीएफ)
- एम पी गुप्ता (2004) ,ई-गवर्नेंस का वादा : परिचालन चुनौतियों , टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रकाशित किया गया था
- कुमार, आर. और बेस्ट, एम. (2006)। "विकासशील देशों में ई-सरकारी सेवाओं का प्रभाव और स्थिरता: तमिलनाडु, भारत से सीखे गए सबक", सूचना सोसायटी, 22, 1-12
- ग्राहम, जे., अमोस, बी. और प्लम्पट्रा, टी. (2003)। "21वीं सदी में सुशासन के सिद्धांत" <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNPAN/UNPAN011842.pdf>

- डब्ल्यूएसआईएस (2017) सूचना सोसायटी पर <https://en.wikipedia.org/wiki/World> समिट पर उपलब्ध
- डिजिटल इंडिया (2017) <http://www.digitalindia.gov.in>
- डिजिटल इंडिया के तहत ई-गवर्नेंस नीति पहल (2015) http://negd.gov.in/writereaddata/files/Digital_Repository/Policy_Document.pdf/
- चक्रवर्ती, एस. (1987). "विकास योजना; भारतीय अनुभव" ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- सीएमएआई (2011) <http://www.cmai.asia/digitalindia/pdf/Digital-India-DeITY-Details.pdf> पर उपलब्ध है
- नीति आयोग (2016) <http://niti.gov.in/content/niti-aayogs-role> पर उपलब्ध
- पांडे, ए.एस. (2004) "ई-गवर्नेंस पर एक उभरती हुई जटिल प्रणाली का परिप्रेक्ष्य", गुप्ता, एम.पी. में "ई-गवर्नमेंट की ओर- प्रबंधन चुनौतियां", टाटा मैकग्रा-हिल नई दिल्ली, पृष्ठ-237-246।
- सतत विकास लक्ष्य-3 पर टास्क फोर्स (2016, 2 दिसंबर)। "इंडिया टुडे" <http://indiatoday.intoday.in/story/task-force-on-sustainable-development-goal-3-formed- govt/1/825398.html>
- सूरी पी.के. और सुशील (2012) "ई-गवर्नेंस की योजना और कार्यान्वयन: एक एसएपी-एलएपी आधारित अंतर विश्लेषण" इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, एन इंटरनेशनल जर्नल 2012, वॉल्यूम 9, नंबर 2 पृष्ठ 178-199,
- तोजा, ए. और तोजा, एस. (2016) "संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए आईसीटी की भूमिका", "मानव विकास को बढ़ावा देने और पर्यावरण की रक्षा के लिए आईसीटी", पृष्ठ 3-13।
- यूएन (2016), "यूनाइटेड नेशंस ई-गवर्नमेंट सर्वे" <http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96407.pdf>
- यूएन (2017), "सतत विकास लक्ष्य" यहां उपलब्ध <http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>
- पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग (1987), "हमारा साझा भविष्य", पृष्ठ 26, <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf> पर उपलब्ध है
- संयुक्त राष्ट्र महिला, वादों को कार्य में बदलना: सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा में लैंगिक समानता (न्यूयॉर्क, 2018)। <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018>
- स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट (2017) <http://niti.gov.in/content/voluntary-national-19> पर उपलब्ध है
- संयुक्त राष्ट्र महिला, विश्व की महिलाओं की प्रगति 2015-2016 अध्याय 2, पृ. 69. संयुक्त राष्ट्र महिला, विश्व की महिलाओं की प्रगति 2015-2016 अध्याय 2, पृ. 69.